

१२२११५

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम  
जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए (2)

२६/११/१८ व कुलार परिषद नठपण संक्षेप में  
ताथ्य इस प्रकार है कि जयगिण नै दिनांक  
१३/११/१७ को विरुद्ध अपानगिण प्रापनापत्ता  
अन्तर्गत धारा १२२११५ इस आबय  
का पेश किया कि सुन्दरसिंह पुत्र  
श्री बदरसिंह के कुल पांच पुत्र क्रमशः  
मेहरसिंह, केहरसिंह, शेरसिंह, दारासिंह, इन्द्रसिंह  
पुत्र हुए। श्री सुन्दरसिंह के दो विवाह  
हए थे। श्री सुन्दरसिंह की प्रथम पत्नि  
का पेश किया एक पुत्र चननसिंह का  
जिसके हालांकि श्री सुन्दरसिंह की द्वितीय  
विवाह की पत्नि श्रीमति प्रताप कौर से पेश  
हए पुत्रों ने इसे सुन्दरसिंह का पुत्र  
होने से इन्कार किया परन्तु अब तक  
चली मुकदमे बाजी में विभिन्न न्यायालयों  
में चननसिंह को सुन्दरसिंह का पुत्र  
होने के निर्णय को बहाल रखा है। इस  
प्रकार स्वर्गीय श्री सुन्दरसिंह के कुल  
६ पुत्र होने का ताथ्य स्वीकृत हुआ है।  
सुन्दरसिंह की स्व. अर्जित चक्र नं० १२७२४  
के फ नं० १५/२५ व १५/२५ व चक्र नं० १५१००  
के फ नं० ६१/२६८, ६०/२६९, ६०/२६८, ६०/२६९,  
५९/२६८, ५९/२६९ की कुल पाबीषा कृषिभूमि  
थी। सुन्दरसिंह के पुत्राण सर्व श्री  
चननसिंह, मेहरसिंह, केहरसिंह, व शेरसिंह  
सम्बन्धित परिवार से पूर्व में अलग हो चुके  
थे जिनके नाम पिता ने अन्य कृषि  
भूमि भी आवंटित करवा दी थी। ऐसे पुत्रों  
की हैसियत विभक्त पुत्रों की थी। श्री  
सुन्दरसिंह ने अपने शेष दो पुत्रों सर्व श्री

(६६)  
सहायक कलक्टर  
एवं उपसप्टाधिकारी  
मुम्बई नगर

दारी सिंह व इन्दु सिंह के पक्ष में समान  
विभाजन के आशय से संवय को आवंटित  
कृषि भूमि कुल ५१ बीघा की वसीयत  
दिनांक १॥६५ व १५॥६७ फंजीकृत कासा ३॥  
जिनके आधार पर सर्व श्री दारी सिंह व  
इन्दु सिंह के नाम इस भूमि के दिनांक  
१॥॥॥७५ को पदत लातेदारी अधिकारों के  
अनुसरण में बतौर लातेदार कृषक इत्तकाल  
कई हुआ। श्री सुन्दर सिंह की जिवित  
अवस्था में श्री सुन्दर सिंह के पुत्रगण  
सर्व श्री नेहर सिंह, मेहर सिंह, शेर सिंह,  
ने अपने पिता सुन्दर सिंह, दारु सिंह व  
इन्दु सिंह के विशुद्ध घोषणात्मक आशापत्र  
द्वे पश्चात कृषि भूमि को पंक्क होना  
मानकर व बदना सिंह से सुन्दर सिंह  
को न्यायगत होने का कब्रन कर इस  
कुल ५१ बीघा भूमि में से १० बीघा  
१० बिस्वा भूमि का संवय को लतेदार  
कृषक घोषित करवाना चाहा। ततपश्चात्  
श्री चरण सिंह के वारिसान संतकोर आदि  
ने इस भूमि में अपना हक होना मानकर  
चरण सिंह के पौत के पश्चात् संवय का  
उनका उत्तराधिकारी होना अभिव्यक्त कर  
बतौर प्राथमिक संयोजित होने का अनुतोष  
चाहा। इन व्यक्तियों के आवेदन पर  
चरण सिंह की पत्नि खेतनोर व पुत्रगण  
सर्व श्री मुख्त्यार सिंह, जगतार सिंह, मंगतराम  
व मिश्रराम को बतौर प्राथमिक संयोजित  
किया गया। श्री सुन्दर सिंह की मृत्यु उक्त

राजस्व वाद की विचारधीन अवस्था में हो गई। विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 13/7/81 के द्वारा दारीसिंह व इन्दसिंह के पक्ष में सुन्दर सिंह के द्वारा निष्पारित वसीयतों को सही मानते हुए वाद निरस्त किया गया। इस निर्णय के विरुद्ध प्राचीण मेहरसिंह आदि ने अपील संख्या 121/81 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर के पत्राचार के समक्ष पेश की जो निर्णय दिनांक 23/7/85 के द्वारा स्वीकार होकर वाद प्राचीण डिब्बी हुआ। यह निर्णय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर, राज उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय तक बहाल रहा। प्रश्नगत कृषि भूमि पर प्राचीण व अपाचीण गण संख्या 15 ता 34 जो कि दारीसिंह व इन्दसिंह के विधिक उत्तराधिकारी गण हैं, अपने पूर्वज श्री सुन्दर सिंह के जीवन काल से ही काबिज चले आ रहे हैं व श्री सुन्दर सिंह की मृत्यु होने के पश्चात से स्वला व निरपेक्ष तौर पर काबिज चले आ रहे हैं। अपाचीण न. 1 ता 14 जो कि सर्वस्त्री मेहरसिंह, केहरसिंह, शेर सिंह व चनण सिंह के वारिस गण हैं, अथवा इनके पिताशों ने कभी भी जरिये प्रतिदावा अथवा संवत्त वाद की जरिए प्राचीण व अपाचीण सं. 15 ता 34 को बेदखल करवाने का कोई अनुतोष नहीं चाहा। ऐसी स्थिति में अपाचीण सं. 1 ता 14 बेदखली का अनुतोष प्राप्त करने के विधिक अधिकार को सर्वव्यक्त्युक्त है व इन अधिकारों का सरा के लिए लोप हो गया है। अपाचीण संख्या 1 ता 14 प्राचीण

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

को प्रशगत कृषि भूमि जो जबरन बेदखल  
 कर देवय काबिज होने के लिए एवं बीजार  
 व्यक्तियों को अन्तर्हित करने के लिए  
 आभार है। पृथम दृष्ट्या मामला सुनिधा  
 को संतुलन व अपरिमेयता के विरु  
 प्रार्थना के पत्र में ही अतः प्रार्थना पत्र  
 मय अपच-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि  
 ता फौसला दावा आस्पाई निषेधादा विरुद्ध  
 अपार्थगण सं। ता। ५ इस आशय का जारी  
 फरमाया जावे कि वे कृषि भूमि चक्र न  
 १२४२४ व १२४२४ कुल पा बीचा को रीगर  
 व्यक्तियों को रहन बस, अथवा अन्य  
 प्रकार से अन्तर्हित करने, इस भूमि पर  
 चले आ रहे प्रार्थगण के शांतिपूर्वक बहजा  
 काश्त व धारण से बिना विधिक प्रक्रिया  
 अपनाये बेदखल करने से एवं इस भूमि  
 के उपयोग व उपभोग के अधिकारों में  
 किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने से निषिद्ध  
 रहे प्रार्थना पत्र के साथ में शपथ-पत्र  
 हरेद्वारे, फोटो प्रति आदेश दिनेम्न ३०/११  
 जमावरी चक्र १२४२४ सम्वत् २०११-१५ व  
 चक्र १२४२४ सम्वत् २०१२ से १५, सम्वत् २०१३  
 से २०१५, आदि पेश किए। प्रार्थना-पत्र  
 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।  
 अपार्थगण को जरिए नोटिस तालब किया  
 गया। दिनांक १५/११/१५ को अपार्थगण न  
 ता ५, ६ ता ८, ११ ता १५ की ओर से प्रार्थना  
 पत्र में संकेत तालबों को अस्वीकार करते  
 हुए जवाब इस आशय का पेश किया कि  
 प्रशगत कुल पा बीचा कृषि भूमि की  
 वसीयत दारासिंह व इन्दुसिंह के पत्र में  
 किए जाने के सबूत का भार प्रार्थगण पर है

(d.w)  
 सहायक कलक्टर  
 एवं उपखण्ड अधिकारी  
 हनुमानगढ़

माननीय उच्च न्यायालय राज जोधपुर व  
 माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा  
 अपने निर्णय में सुन्दर सिंह द्वारा की गई  
 वसीयत का अवैध मानते हुए खारिज की  
 जा चुकी है तथा प्राचीन द्वारा प्रस्तुत अपील  
 को भी माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली  
 द्वारा अपने निर्णय दिनांक ७/११/७२ द्वारा  
 खारिज की जा चुकी है तथा वर्तमान राजस्व  
 रिकार्ड में मिन अप्राचीन व उनके पूर्वजों  
 के नाम उपरोक्त कृषि भूमि प्राचीन के  
 पूर्वजों के साथ संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड  
 में दर्ज है तथा उपरोक्त कृषि भूमि मिन  
 अप्राचीन की पैतृक कृषि भूमि है जिसपर  
 मिन अप्राचीन बतौर खातेदार कार्रवार  
 घोषित किये जाने पर अपनी हक व हिस्सा  
 अनुसार उपरोक्त कृषि भूमि प्राप्त करने के  
 अधिकारी हैं। प्राचीन द्वारा किये गये कथन  
 कि सुन्दर सिंह की मृत्यु के बाद उपरोक्त कृषि  
 भूमि में लगातार उनके काबिज रहने के कथन  
 फतव्व गलत व मात प्राचीन पक्ष को रंगत  
 देने के लिए गलत दर्ज किए हैं। प्रश्नगत कृषि  
 भूमि में प्राचीन व प्राचीन के पूर्वजों के  
 नाम अपने हक व हिस्सा अनुसार ११६ हिस्सा  
 राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज है। जिसे  
 मिन अप्राचीन ने माननीय उच्चतम न्यायालय  
 नई दिल्ली द्वारा पारित अपने निर्णय दिनांक  
 ७/११/७२ द्वारा किये जाने के बाद माननीय  
 न्यायालय के समक्ष उपरोक्त कृषि भूमि को  
 अपने हक व हिस्सानुसार वापस प्राप्त करने  
 की विधि व प्रक्रिया अपनाते हुए प्राचीन पक्ष  
 अर्जत द्वारा १८३६ राजस्वान कार्रवारी अधिनियम  
 प्रस्तुत किया हुआ है। इसलिए प्राचीन मिन  
 अप्राचीन के विरुद्ध किसी भी दार का अनुलोष  
 प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तथा प्राचीन

(६६)

सहायक कलेक्टर  
 एवं उपखण्डाधिकारी  
 हनुमानगढ़

पत्राचारिज किए जाने योग्य है जो खासिब  
 फरमाया जावे। जवाब की तारीख में शायद  
 जंगीरीसहे, जोरो प्रति राज उच्च न्यायालय जोध  
 निर्णय दिनांक 31/10/2007, व जोरो प्रतिमान्नीय  
 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली आदि पेश किए  
 विद्वान अभिभावक उभयपक्ष की बहस सुनी  
 गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
 निम्नान अभिभावक अप्रार्थिगण ने प्रार्थना पत्र  
 में संकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र  
 प्रार्थिगण स्वीकार कर दिनांक 16/11/17 को  
 ता फौसला दावा कनकर्म किए जाने व  
 विद्वान अभिभावक अप्रार्थिगण ने उक्त तर्क  
 का खण्डन करते हुए तथा जवाब में संकित  
 तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को  
 खासिब किए जाने हेतु तर्क प्रस्तुत किया।  
 विद्वान अभिभावक उभयपक्ष की बहस पर  
 मनन करने एवं पत्रावली को गहन अध्ययन  
 करने एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन  
 मनन करने उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है  
 कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थिगण रेकार्ड खोतेपर  
 काश्तकार है, प्रार्थिगण जिस बसीयत के  
 आधार पर अपना हक जता रहे है वह निरस्त  
 हो चुकी है। हकों का निर्धारण मूल वाद में  
 तैय होना है। प्रार्थना पत्र के निस्तारण में केवल  
 यह देखा जाना है कि पृथम इच्छतया प्रकरण  
 सुविधा का सन्तुलन व प्राकृतिक न्याय का  
 सिद्धान्त किसके पक्ष में बनता है। वादग्रस्त  
 भूमि जसिए विरास्त अप्रार्थिगण रेकार्ड खोतेपर  
 काश्तकार है, बसीयत निरस्त हो चुकी है।  
 उपरोक्त विवेचन स्वरूप पृथम इच्छतया प्रकरण  
 सुविधा का सन्तुलन व प्राकृतिक न्याय का  
 सिद्धान्त अप्रार्थिगण के पक्ष में पाया जाता है।  
 प्रार्थना पत्र प्रार्थिगण का बिल खासिब है।  
 द्वातः प्रार्थना पत्र प्रार्थिगण दिनांक 16/11/17 का  
 जारी स्वगन् आदेश निरस्त करते हुए खासिब  
 किया जाता है। पत्रावली नम्बर से काम की  
 जाकर वाद तरतीब तक्रामील जाबता दाखिल  
 दफ्तर है। आदेश आज दिनांक 26/11/18 को बहस  
 इजलास सुनाया गया। (6)

संतुलक न्याय  
 एवं उपखण्डाधिकारी  
 न्यायमंडल

